शंघाई में हालात बेकाबू

इस नीति के तहत लॉकडाउन और क्वारंटीन के सख्त प्रावधानों की वजह से शंघाई में लोगों के घर के अंदर भूख से मरने की नौबत आ गई है क्योंकि उन्हें खाने के सामान घर पर आसानी से नहीं मिल रहे हैं।

ममता सिंह।।

कोरोना की स्थिति तो दुनिया के कई देशों में गंभीर बनी हुई है, लेकिन चीन से आ रही खबरें विशेष चिंताजनक हैं। खास तौर पर चीन के एक बड़े व्यावसायिक केंद्र शंघाई में लोग जिस तरह के हालात से जूझ रहे हैं, वे महामारी से अधिक उससे निपटने के अंदाज पर सवाल खड़े करते हैं। शंघाई में पिछले महीने संक्रमण में तेजी आने के बाद कोरोना प्रोटोकॉल से जुड़े सारे प्रावधान पूरी कड़ाई से लागू कर दिए गए। पिछले करीब 22 दिनों के सख्त लॉकडाउन के बावजूद नए केसों की संख्या काबू में आती नहीं दिख रही। शनिवार को वहां 23,000 और रविवार को 25,000 कोविड के केस मिले। ढाई करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस शहर में संक्रमण की यह स्थिति बहुत खराब नहीं कही जाएगी। भारत और दुनिया के कई देश इससे गंभीर परिस्थितियों से निपट चुके हैं। लेकिन चीन जीरो कोविड नीति से पीछे हटने को तैयार नहीं। इस नीति के तहत लॉकडाउन और क्वारंटीन के सख्त प्रावधानों की वजह से शंघाई में लोगों के घर के अंदर भूख से मरने की नौबत आ गई है क्योंकि उन्हें खाने के सामान घर पर आसानी से नहीं मिल रहे हैं।

हॉस्पिटल्स में स्वास्थ्यकर्मियों की कमी है। इसलिए मरीजों की ठीक से देखभाल नहीं हो पा रही। यह स्थिति तब है, जब इस बार कोरोना के ज्यादातर मामले ओमीक्रॉन वेरिएंट के बताए जा रहे हैं, जिनमें मरीजों की मौत काफी कम देखी जाती है। यहां हम दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले चीन में कोरोना से निपटने की नीति में एक बुनियादी अंतर देख सकते हैं। बाकी देश अब कोरोना को एक हकीकत मानकर उसके साथ रहना सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके विपरीत चीन पूरी तरह से कोविड पर काबू पाने की नीति पर चल रहा है। शुरू में उसे इसका फायदा भी मिला था। कोरोना की शुरुआती लहर पर चीन ने बहुत जल्द काबू पा लिया था। न्यूजीलैंड जैसे देशों ने भी पहले पहल ऐसी ही नीति अपनाई थी। बाद में इसके आर्थिक दुष्प्रभावों को देखते हुए उन देशों ने इस नीति पर चलना छोड़ दिया। चीन अभी तक जीरो कोविड की नीति पर चल रहा है। वह इसे अमेरिका जैसे देशों के मुकाबले बेहतर बताता आया है, जहां चीन की तुलना में महामारी से कहीं अधिक मौतें हुई हैं। लेकिन चीन की इस नीति से जहां नागरिकों की जिंदगी प्रभावित हो रही है, वहीं अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। विश्व बैंक 2022 में चीन की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर को घटाकर पांच फीसदी कर चुका है। पिछले साल यह 8.1 फीसदी थी।

चीन के सख्त लॉकडाउन से ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी बुरा असर हुआ है। इससे खासतौर पर विकसित देशों में महंगाई बढ़ रही है। अच्छा हो, अगर चीन भी बाकी दुनिया की तरह कोविड के साथ जीना सीख ले।

वास्तुदोष

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा। गलत दिशा में रखी गईं धार्मिक पुस्तकें वास्तु दोष का कारण बनती हैं। वास्तु के अनुसार धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों को हमेशा पश्चिम की तरफ ही रखना चाहिए। किसी दूसरी दिशा में,बेड के अंदर अथवा गद्दे या तकिये के नीचे धार्मिक पुस्तकें रखना शुभ नहीं होता । वास्तुदोष के कारण यदि घर में किसी सदस्य को रात में नींद नहीं आती या स्वभाव चिडचिडा रहता हो, तो उसे दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके शयन कराएं। इससे उसके स्वभाव में बदलाव होगा और अनिद्रा की स्थिति में भी सुधार होगा। घर में किसी भी कमरे में सूखे हुए पुष्प नहीं रखने दें। यदि छोटे गुलदस्ते में रखे हुए फूल सूख जाएं, तो नए फूल लगा दें और सूखे पुष्पों को निकालकर बाहर फेंक दें। वास्तु शास्त्र में पेड़–पौधों के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है।

संपादकीय

आगे की राह

मैक्रों के लिए इससे भी बड़ी चुनौती फ्रांस में बढ़ते और तीखे होते राजनीतिक–वैचारिक ध्रुवीकरण, सामाजिक–धार्मिक टकराव और श्रमिक तथा निम्न मध्यवर्गीय समूहों में बेचैनी के बीच अर्थव्यवस्था को संभालने, लोगों को महंगाई से राहत दिलाने और राजनीति में समझौते तथा सहयोग की जमीन तलाशने की होगी। रूस–यूक्रेन युद्ध ने मैक्रों की परेशानियां और बढ़ा दी हैं, जिसके जारी रहने से अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाने की आशंका है। फ्रांस ने पिछले चार सालों में इन मुद्दों को लेकर जुझारू 'येलो–वेस्ट' आंदोलन देखा है। इन बातों का असर जून में होने वाले संसदीय चुनावों पर भी पड़ सकता है, जहां अभी उनकी रिपब्लिक ऑन द मूव (लारेम) पार्टी को भारी बहुमत हासिल है। दूसरे कार्यकाल में सुधारों और अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए मैक्रों को जून के संसदीय चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करना और बहुमत बनाए रखना होगा, जहां उनका मुकाबला हार के बावजूद इन नतीजों से उत्साहित और आक्रामक ली पेन की नेशनल रैली पार्टी और वामपंथी खेमे से होगी। मुश्किल यह है कि धुर दक्षिणपंथी उभार से निपटने के लिए जहां मैक्रों खुद दक्षिण की ओर झुक रहे हैं, वहीं मरीन ली पेन अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए कुछ हद तक मॉडरेट रुख अख्तियार कर रही हैं। मैक्रों को अंदाजा है कि फ्रेंच आबादी के एक बड़े हिस्से खासकर युवाओं, श्रमिकों, प्रवासियों और अल्पसंख्यकों में गहरी बेचैनी और असंतोष है, जिसे साधना आसान नहीं होगा। उनके अगले पांच साल राजनीतिक रूप से कठिन रहने वाले हैं। मुश्किल यह है कि मैक्रों के गले के ठीक नीचे धुर दक्षिणपंथी खेमा और मरीन ली पेन उनकी नाकामी का इंतजार कर रही हैं।

मैक्रों ने 2017 की तरह एक बार फिर धुर दक्षिणपंथी नेता मरीन ली पेन को हराया है, लेकिन इस बार उनकी जीत का अंतर आधे से भी कम रह गया। मैक्रों को पिछले चुनावों में 66 फीसदी वोट मिले थे।

पश्चिमी देश खुश

आनंद प्रधान।।

फ्रांस के राष्ट्रपति चुनावों में बड़े उलटफेर की आशंकाओं के बीच उदार–मध्यमार्गी इमैनुएल मैक्रों दोबारा चुनाव जीत गए हैं। पिछले दो दशकों में लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने वाले वह फ्रांस के पहले राष्ट्रपति हैं। मैक्रों ने 2017 की तरह एक बार फिर धुर दक्षिणपंथी नेता मरीन ली पेन को हराया है, लेकिन इस बार उनकी जीत का अंतर आधे से भी कम रह गया। मैक्रों को पिछले चुनावों में 66 फीसदी वोट मिले थे। इस बार उन्हें 8 फीसदी कम लगभग 58 फीसदी वोट मिले हैं, जबकि मरीन ली पेन को पिछली बार के करीब 33 फीसदी वोटों की तुलना में इस बार 8 फीसदी ज्यादा लगभग 41 फीसदी वोट मिले।

मैक्रों की जीत से वॉशिंग्टन से लेकर यूरोपीय संघ के मुख्यालय– ब्रसेल्स तक ज्यादातर पश्चिमी देशों की राजधानियों में राजनेताओं ने राहत की सांस ली है। इसकी वजह यह है कि इन चुनावों में न सिर्फ यूरोपीय संघ और नैटो का भविष्य दांव पर लगा था बल्कि रूस–यूक्रेन युद्ध के बीच पश्चिमी देशों की एकता भी खतरे में दिख रही थी। असल में, मरीन ली पेन न सिर्फ यूरोपीय संघ और नैटो की विरोधी रही हैं बल्कि वह रूस और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन की करीबी मानी जाती हैं। यही नहीं, ली पेन यूरोप में वैसी राजनीति करती हैं, जो प्रवासियों

को खुलेआम निशाना बनाती है और गहरे 'इस्लामोफोबिया' से ग्रस्त है। याद रहे कि यूरोप में फ्रांस में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है।

माना जा रहा था कि ली पेन की जीत यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर आने यानी ब्रेक्जिट के धक्के के बाद फ्रांस के उससे बाहर निकलने यानी फ्रेक्जिट तक का रास्ता खोल सकती थी, जो आर्थिक–राजनीतिक रूप से एकीकृत यूरोप के विचार के लिए मरणान्तक धक्का साबित हो सकता था। ली पेन की जीत अमेरिकी–यूरोपीय सैन्य गठबंधन– नैटो के अंदर मतभेद बढ़ाकर उसे कमजोर कर सकती थी। इन आशंकाओं ने यूरोपीय संघ से लेकर नैटो तक के नेतृत्व की नींद उड़ा रखी थी क्योंकि फ्रांस न सिर्फ यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है बल्कि वह एक परमाणु–शक्ति संपन्न सैन्य ताकत और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य भी है।

इस अर्थ में, यह चुनाव सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में उदार–मध्यमार्गी बनाम धुर दक्षिणपंथी राजनीति के बीच एक वैचारिक युद्ध में बदल गया था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहली बार इस चुनाव में जर्मनी के चांसलर और स्पेन तथा पुर्तगाल के प्रधानमंत्रियों ने फ्रांस के जाने–माने अखबार– 'ल मांद' में एक संयुक्त लेख लिखकर फ्रेंच वोटरों से 'पॉप्युलिस्ट और धुर दक्षिणपंथी राजनीति' के खतरे से सावधान रहने और परोक्ष रूप से मैक्रों को जिताने की अपील की। आमतौर पर किसी देश के राष्ट्रीय चुनावों में दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष ऐसे हस्तक्षेप नहीं करते, जैसा फ्रांस के चुनावों में इस बार दिखा।

हालांकि चुनावी नतीजों से ऐसा लगता है कि तीखे राजनीतिक–वैचारिक ध्रुवीकरण और ली पेन की जीत के डर ने आखिरकार इन वोटरों को भी घर से निकलने और मैक्रों को वोट डालने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बावजूद वोटरों का एक हिस्सा वोट देने नहीं निकला, जिसके कारण 1969 के बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनावों में इतनी कम वोटिंग हुई। खुद मैक्रों ने जीत के बाद दिए भाषण में माना कि उन्हें उन लोगों ने भी वोट दिया, जो उनकी नीतियों से सहमत नहीं हैं। इसका अर्थ यह है कि जीतने के बावजूद मैक्रों इन वोटरों के समर्थन को लेकर निश्चिंत नहीं हो सकते। दूसरे, जीत के बावजूद उनकी राजनीतिक पूंजी कम हुई है।

अष्टयोग-5068

		4	3			1
2	34	7	30		28	
		1	6		5	4
3	31		32	6	33	
	5	3			2	7
5	28		33	7	38	
1		2		5		6

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5067 का हल

3	1	4	6	2	5	7
5	32	7	32	1	30	3
1	6	5	4	3	7	2
2	35	3	35	7	32	6
7	5	6	3	4	2	1
6	34	1	34	5	28	4
4	3	2	7	6	1	5

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

कसाब तो था भी पाकिस्तानी...

मोहन। मैं सोचने लगा कि अगर तस्वीरों में दिखने भर से सरकारों को प्देजंदज इंसाफ की छूट मिल जाती है तो इस हिसाब से अजमल आमिर कसाब को तो अगले दिन ही फांसी हो जानी चाहिए थी। यहां तो मामला साम्प्रदायिक हिंसा में कुछ लोगों के घायल होने और पत्थरबाजी का था। लेकिन 26/11 को मुम्बई पर हुआ आतंकी हमला तो भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। यहां तो हिंसा में शामिल लोग अपने देश के थे, कसाब तो था भी पाकिस्तानी। फिर भी भारत सरकार ने प्देजंदज इंसाफ करते हुए फांसी देने के उसे वकील रखने की छूट दी। सालों साल अदालत में उस पर मुकदमा चला। दोषी साबित होने पर उसने ऊपरी अदालत में अपील भी की। वहां भी सजा कम नहीं हुई, राष्ट्रपति के पास माफी का आवेदन भी भेजा और जब वो दया याचिका भी खारिज हो गई तब जाकर उसको फांसी हुई।